भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 874

07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

शिक्षक छात्र अनुपात

874. श्री सुधीर गुप्ता:

श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या भारतीय भेषजी परिषद (पीसीआई) ने पूर्व के शिक्षक और छात्र अनुपात को 1:15 से बदलकर आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी. फार्मा) पाठ्यक्रमों के लिए अधिकतम शिक्षक-छात्र अनुपात 1:24 और दो वर्षीय डी.फार्मा कार्यक्रम के लिए 1:24 का होना अनिवार्य कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पीसीआई ने बी.फार्मा और डी.फार्मा डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने वाले हितधारकों और निजी महाविद्यालयों के साथ कोई परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या शिक्षकों ने यह आरोप लगाते हुए पीसीआई के उक्त कदम की आलोचना की है कि इसके परिणामस्वरूप शिक्षकों की भर्ती कम होगी जिससे रोजगार में कमी आएगी और शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में भेषज क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): भारतीय भेषजी परिषद के शिक्षा विनियम, 2020 के अनुसार, डी.फार्मा कोर्स के लिए स्टाफ और छात्र का अनुपात सैद्धांतिक कक्षाओं में 1:60 और व्यावहारिक कक्षाओं में 1:20 से अधिक नहीं होना चाहिए। हालाँकि, बैचलर ऑफ़ फ़ार्मेसी (बी.फार्मा) कोर्स विनियम, 2014 में स्टाफ और छात्र के अनुपात को निर्दिष्ट नहीं किया गया था।

इसके बाद, विभिन्न राज्यों के हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदन को ध्यान में रखते हुए, भारतीय भेषजी परिषद ने अपने परिपत्र संख्या 5323 दिनांक 09.01.2025 के माध्यम से निर्धारित किया कि बी.फार्मा कोर्स में सैद्धांतिक कक्षाओं और व्यावहारिक कक्षाओं में स्टाफ और छात्र का अनुपात 1:20 से अधिक नहीं होना चाहिए। यह भी बताया गया कि पहले भी न तो शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:24 था और न ही 1:15। पीसीआई ने बताया कि किसी भी शिक्षक ने पीसीआई के इस कदम की आलोचना नहीं की है।

(घ): फार्मेसी क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं जैसे शिक्षण और व्यावसायिक गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिए आधार प्रमाणीकरण प्रणाली का कार्यान्वयन, फार्मासिस्टों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए एकल खिड़की प्रणाली का निर्माण, फार्मा सह-सतर्कता केंद्र स्थापित करने और दवा सुरक्षा की निगरानी के लिए भारतीय भेषज संहिता आयोग (आईपीसी) के साथ सहयोग, फार्मेसी संस्थानों की निरीक्षण प्रक्रिया में नवाचार और प्रौद्योगिकी को अपनाना, बी.फार्मा पाठ्यक्रम में संशोधन, पारदर्शी पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए संकाय और छात्र पोर्टल की शुरुआत, भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के सहयोग से फार्मेसी शिक्षा संस्थानों के लिए मूल्यांकन और रेटिंग प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव।

*****